किसान सशक्त होता है तो गाँव, प्रदेश व देश प्रगति करता है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने सिरोही में किसान सम्मान निधि हस्तानांतरण किया व ग्राम उत्थान शिविर का शुभारंभ किया

जयपुर/सिरोही/जालोर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान भारत की आत्मा है। जब किसान सशक्त होता है तो गांव, प्रदेश और देश प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र में किए गए वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं तथा हमारी सरकार किसानों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही में कार्यक्रम स्थल पर आयोजित कृषि प्रदर्शनी में सहकारिता, पशुपालन, एफपीओ एवं प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी और एग्री स्टार्टअप सहित अन्य स्टालों का अवलोकन किया।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को सिरोही में किसान सम्मान निधि के हस्तानान्तरण एवं ग्राम उत्थान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोगाराम कुमावत, जालोर-सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी मौजूद थे।

कि 23 जनवरी (बसंत पंचमी) से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर ग्राम उत्थान शिविरों को आयोजन किया जाएगा।

शर्मा गुरूवार को सिरोही में किसान सम्मान निधि के हस्तानान्तरण एवं ग्राम उत्थान शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन दो वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत एवं दशकों से लंबित मांग को पूरा कर अयोध्या में रामलला की प्राणप्रतिष्ठा की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदेश के एक करोड़ से अधिक किसान, महिला एवं श्रमिक लाभार्थियों को 1 हजार 590 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी। उन्होंने 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की पांचवीं किस्त के रूप में प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी की, साथ ही 5 लाख किसानों को फसल खराबे पर 327 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया।

शर्मा ने समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 10 हजार से अधिक किसानों को 240 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई तथा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ की राशि भेजी गई। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को 75 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्रदान की गई तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के 20 हजार लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने एक लाख निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान 40 करोड़ रुपये के कृषि उपकरणों का वितरण भी किया गया।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्ष में सिरोही को विकास के लिए अनेक सौगातें दी हैं।

इस दौरान ग्राम उत्थान शिविरों का लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से शुभारंभ किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित कृषि प्रदर्शनी में सहकारिता, पशुपालन, एफपीओ एवं प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी एवं एग्री-स्टार्टअप सहित, अन्य स्टॉल्स का अवलोकन किया।

कार्यक्रम में रामलला प्रतिमा का विधिवत पूजन किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने राजस्थान के मूल निवासी एवं महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत राज के. पुरोहित को पुष्पांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधायक समाराम गरासिया, पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, जीवाराम चौधरी, शोभा चौहान, छगनसिंह राजपुरोहित, हमीर सिंह भायल सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित थे।

डोडा सड़क हादसे में दस जवान शहीद

जम्मू, 22 जनवरी। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे में सेना के एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से 10 जवानों की मौत हो गयी और 11 अन्य घायल हो गए।

यहां अधिकारियों ने बताया कि सेना का कैस्पर वाहन भद्रवाह-चंबा सड़क पर थानाला के ऊपरी इलाके खन्नीटॉप के पास फिसलन भरी सड़क के कारण, करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। यह टीम एक टीम ऑपरेशन

- **सैन्य दल एक कार्यवाही के लिए जा रहा था खन्नी टॉप के पास सेना का वाहन 300 फीट गहरी खाई में गिर गया।**

के लिए जा रही थी। यह हादसा इतना भयावह था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिला प्रशासन के अनुसार, वाहन में सेना के कुल 21 जवान सवार थे, जिनमें से 10 की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 10 जवानों को ऊधमपुर के कमांड अस्पताल में तत्काल उपचार के लिए एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि मामूली रूप से घायल एक जवान का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उपराज्यपाल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश एकजुट होकर उनके साथ खड़ा है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हृदय विदारक त्रासदी पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने इस घटना को पूरे जम्मू-कश्मीर के लिए एक बड़ी त्रासदी बताते हुए प्रशासन को घायलों के उपचार में कोई कसर न छोड़ने के निर्देश दिए।

केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस दुखद दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा है।

मुम्बई, पुणे सहित 15 मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित

राज्य सरकार ने 29 प्रमुख महानगर पालिकाओं के मेयर पद के लिए आरक्षण योजना घोषित की

मुंबई, 22 जनवरी। महाराष्ट्र की राजनीति में स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। राज्य की 29 प्रमुख महानगरपालिकाओं के महापौर पद के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। इस बार के आरक्षण समीकरणों ने राज्य की 15 महानगरपालिकाओं की कमान महिलाओं के हाथों में सौंप दी है। मुंबई, पुणे, नागपुर और नवी मुंबई जैसे हाई-प्रोफाइल शहरों में अब सामान्य महिला वर्ग की महापौर चुनी जाएंगी।

29 में से 12 सीटें एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 17 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। शिंदे के गढ़ ठाणे में महापौर एससी कैटेगरी का होगा। मुंबई में 8वीं बार किसी महिला को यह पद मिलेगा। इससे पहले किशोरी पेडनेकर मेयर थीं।

- **आरक्षण की घोषणा होते ही महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। शिवसेना (यूबीटी) ने इस व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह जताया।**

आरक्षण की घोषणा होते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) की नेता और पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर ने मुंबई महानगरपालिका के आरक्षण पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने सवाल उठाया कि ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के समय मुंबई महापालिका की पर्ची क्यों नहीं डाली गई?

उन्होंने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह व्यक्त किया है।

दूसरी ओर, नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने इन आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत अपनाई गई है और इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हुआ है।

इस आरक्षण घोषणा के साथ ही, सभी राजनीतिक दलों ने महिला उम्मीदवारों की तलाश और चुनावी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। विशेष रूप से मुंबई और पुणे जैसे शहरों में महिला पार्षदों का कद अब राजनीति में और बढ़ने वाला है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को ''ज़ैड'' सुरक्षा, तेजस्वी की सुरक्षा घटाई

बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव किए हैं

- **भाजपा व जद यू के कई वरिष्ठ नेताओं को ज़ैड सुरक्षा दी गई है, वहीं विपक्ष के कई नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई है।**

पटना, 22 जनवरी। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के कई दिग्गज विधायकों की सुरक्षा श्रेणी में बड़ा बदलाव किया है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति की ताजा रिपोर्ट और खुफिया इनपुट्स के आधार पर लिए गए इस फैसले में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने तेजस्वी की सुरक्षा घटा दी है, वहीं भाजपा और केन्द्र सरकार के कई मंत्रियों का सुरक्षा घेरा पहले से अधिक मजबूत कर दिया गया है।

सुरक्षा समिति की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम कर दी गई है। अब तक उन्हें 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही थी, जिसे घटाकर अब 'वाय प्लस' कर दिया गया है। इसके साथ ही, तीन अन्य वरिष्ठ नेताओं मदन मोहन झा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और राजेश राम की सुरक्षा पूरी तरह से वापस ले ली गई है। एक ओर जहाँ विपक्ष की सुरक्षा में कटौती हुई है, वहीं सत्ता पक्ष के कई रसूखदार चेहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और बिहार सरकार के मंत्रियों को अब और भी कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केन्द्रीय मंत्री लल्लन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इन्हें वाई से बढ़ाकर वाई प्लस और फिर सुरक्षा मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया गया है।

ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकियां नाकामयाब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और ही कहानी कहते हैं। यह सोच-समझकर उठाया कदम नहीं, बल्कि मजबूरी में किया गया फैसला था।

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प का दांव उनकी चरम तक जाने की चिरपरिचित शैली का उदाहरण था। अमेरिका के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से उछाली, कभी अस्पष्ट, कभी भड़काने वाले अंदाज़ में उन्होंने अटलांटिक पार संबंधों में अनिश्चितता पैदा कर दी। भले ही बाद में उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अमेरिका बल प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन उनका यह दावा कि ''ग्रीनलैंड की रक्षा केवल अमेरिका ही कर सकता है'', डेनमार्क और यूरोप की संप्रभुता पर अमेरिकी वर्चस्व की एकतरफा घोषणा जैसा था।

यूरोप की प्रतिक्रिया आक्रोश से भरी थी, पर वे इसका हल चाहते थे। डेनमार्क ने ट्रंप के विचार को सिरे से खारिज कर दिया, यूरोपीय संघ ने चुपचाप लेकिन सख़्ती से कदम उठाया तथा वॉशिंगटन के साथ व्यापार समझौते के क्रियान्वयन को रोक दिया। नाटो सहयोगी इस सिद्धांत पर एकजुट हो गए कि आर्कटिक सुरक्षा किसी एक शक्ति द्वारा तय नहीं की जा सकती, चाहे वह कितनी ही प्रभावशाली क्यों न हो। यूरोप को झुकाने के लिए दी गई ट्रम्प की टैरिफ धमकियाँ भी इस एकता को तोड़ने में नाकाम रहीं।

नतीजतन कूटनीति के नाम पर उन्हें यू-टर्न लेना पड़ा। वास्तविक समझौते के बजाय भविष्य के समझौते का ढांचा घोषित करके ट्रम्प ने प्रभावी रूप से मानक नीचे कर दिया। टैरिफ इसलिए निलंबित नहीं हुए कि यूरोप ने ग्रीनलैंड पर कोई रियायत दी, बल्कि इसलिए कि टकराव एक बंद गली में पहुँच चुका था। इस ढांचे ने ट्रम्प को प्रगति का दावा करने का अवसर दिया वो भी बिना स्वामित्व, सैन्य ठिकानों या औपचारिक नियंत्रण के, सिर्फ नाटो के मौजूदा ढांचे के तहत अस्पष्ट सहयोग के साथ।

दावोस में ट्रम्प का एक घंटे का भाषण प्रभुत्व दिखाने के लिए था, लेकिन उसने उनके रुख के अंतर्विरोधों को और उजागर कर दिया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी भूमिका का हवाला देकर डेनमार्क को ''कृतघ्न'' कहा और आज के दावों को सही ठहराने के लिए ऐतिहासिक शिकायतों का हवाला दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को सिर्फ सुरक्षा के लिए चाहता है, खनिजों के लिए नहीं, जबकि उनकी सरकार अन्य जगहों पर संसाधन-राष्ट्रवाद का समर्थन करती रही है।

सबसे उल्लेखनीय यह कि उन्होंने फिर दोहराया कि अमेरिका को नाटो से ''कुछ भी नहीं मिलता'', सिवाय यूरोप की रक्षा का बोझ उठाने के। यह तर्क, जो उनके पहले कार्यकाल में भी था। पर अब और भी खोखला लगता है। अगर नाटो से अमेरिका को कुछ नहीं मिलता, तो आर्कटिक सुरक्षा पर उसके महासचिव के जरिए बातचीत क्यों? नाटो-प्रायोजित ढांचे की ज़रूरत ही क्यों?

क्योंकि एकतरफावाद के पास कोई रास्ता नहीं बचा था।

ट्रम्प ने संबोधन दावोस के श्रोताओं में ''दोस्तों'' और ''कुछ छिपे दुश्मनों'' पर मज़ाक किया। लेकिन हँसी के पीछे असहजता छिपी थी। यूरोपीय नेताओं ने किसी माहिर सौदेबाज़ को नहीं, बल्कि ऐसे राष्ट्रपति को देखा, जिसे सामूहिक प्रतिरोध मज़बूत होते ही धमकियों से पीछे हटना पड़ा।

ग्रीनलैंड प्रकरण में ट्रम्प की मिसाइल रक्षा को लेकर फिर से उभरी दीवानगी, खासकर उनके प्रस्तावित गोल्डन डोम एंटी-मिसाइल शील्ड पर भी रोशनी डालता है। रूस के निकट होना, रडार की क्षमता और आर्कटिक पहुँच, ग्रीनलैंड की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति इस सोच में फिट बैठती है। लेकिन यहाँ भी ट्रम्प ने हद से ज़्यादा दांव खेला।

ग्रीनलैंड को लगभग पूरी तरह अमेरिकी सुरक्षा दृष्टिकोण से परिभाषित करके ट्रम्प ने डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड की स्वायत्त सरकार के हितों को भी हाशिये पर डाल दिया। यह रवैया उनके घरेलू समर्थकों को भा सकता है, लेकिन विदेशों में वैधता को कमज़ोर करता है। आर्कटिक की सुरक्षा संरचनाएँ स्वभावत: बहुपक्षीय हैं, इसके विपरीत दिखावा करना केवल विरोध को मज़बूत करता है।

असल में, ट्रम्प ने रणनीतिक चिंता को क्षेत्रीय दबाव में बदलने की कोशिश की और पाया कि सहयोगियों की भी अपनी सीमाएँ होती हैं।

ट्रम्प बेनकाब हुए हैं? लेकिन न तो घातक रूप से और न ही अपरिवर्तनीय रूप से। ट्रम्प तीन तरह से बेनकाब हुए हैं।

पहला, वे एक ऐसे ब्लफ़र के रूप में उजागर हुए हैं जिनकी धमकियों को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए लगातार बढ़ती आक्रामकता चाहिए। जब टैरिफ अस्थिर हो गए और कूटनीतिक अलगाव का खतरा मंडराने लगा, तो उन्हें ठोस जीत के बजाय प्रतीकात्मक ढांचे पर संतोष करना पड़ा।

दूसरा, वे उन संस्थानों पर निर्भर दिखे, जिन्हें वे सार्वजनिक रूप से तिरस्कृत करते हैं। वर्षों तक नाटो की आलोचना के बाद उसी पर उनकी निर्भरता एक संरचनात्मक सच्चाई को उजागर करती है: अमेरिकी शक्ति गठबंधनों के जरिए बढ़ती है, उनके बिना नहीं।

तीसरा, संप्रभुता के मामलों में लेन-देन आधारित कूटनीति की सीमाएँ उजागर हुईं। यूरोप व्यापार शर्तों पर बातचीत कर सकता है, पर दबाव में क्षेत्र नहीं सौंपेगा।

फिर भी, ट्रम्प ने जीवित रहने की राजनीतिक प्रवृत्ति भी दिखाई। स्थायी टूट से पहले पीछे हटकर उन्होंने एक गहरे अटलांटिक संकट से बचाव कर लिया। उनका समर्थक वर्ग इसे चुनौती के रूप में सुनेगा; बाज़ार स्थिरता के रूप में, सहयोगी एक चेतावनी, लेकिन साथ में राहते के रूप में।

ग्रीनलैंड पर यू-टर्न सिर्फ आर्कटिक की ज़मीन के बारे में नहीं है बल्कि यह ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की एक व्यापक सच्चाई को दर्शाता है कि बयानबाज़ी और वास्तविकता के बीच की खाई सिमट रही है। दुनिया अब ज़्यादा तैयार, ज़्यादा संगठित है और पहले की तुलना में इसे ज्यादा डराया नहीं जा सकता।

खासतौर पर यूरोप ने सीख लिया है कि संयम और एकता का मेल दबाव को निष्प्रभावी कर सकता है। ट्रम्प भले ही झटकों और तमाशे से एजेंडा तय करते रहें, लेकिन नतीजे अब अधिकतर बातचीत से, कमज़ोर होकर या टलकर सामने आएँगे।

इस अर्थ में, यह प्रकरण हार से ज़्यादा एक खुलासा है। यह दिखाता है कि ट्रम्प कैसे काम करते हैं और वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। ग्रीनलैंड ताकत का प्रदर्शन होना था, लेकिन अंतत: यह सीमाओं का अध्ययन बन गया।

और उस राष्ट्रपति के लिए, जो असीमित दबाव की धारणा पर फलता-फूलता है, इससे ज़्यादा असहज खुलासा शायद कोई और नहीं।

मध्य प्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हिंदू समुदाय भोजशाला, 11वीं शताब्दी के इस स्मारक, को वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है।

2003 के ए एस आई आदेश के अनुसार, मुसलमानों को इस स्थल पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमा की नमाज़ अदा करने की अनुमति है, जबकि हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पारंपरिक अनुष्ठान करने और प्रत्येक मंगलवार को विशेष प्रवेश का अधिकार दिया गया है।

लेकिन, इस आदेश में उन वर्षों के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती हो। और 23 जनवरी ऐसा केवल चौथा अवसर है, इससे पहले यह संयोग 2006, 2013 और 2016 में हुआ था।

बसंत पंचमी से पहले धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

मध्य प्रदेश के इस जिले में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स सहित लगभग 8,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

पुलिस पैदल और वाहन गश्त कर रही है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है।

इसके अलावा, पूरे शहर में सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।

आयरन फैक्ट्री में भयानक विस्फोट, 6 मजदूरों की मौत

बलौदाबाजार, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना में कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई है और 10 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं।

ये घटना भाटापारा क्षेत्र में स्थित प्राइवेट इस्पात स्पंज आयरन फैक्ट्री में

- **छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुए हादसे में भयानक विस्फोट के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में दस मजदूरों के घायल होने की भी खबर है।**

हुई है। आज (गुरुवार) सुबह लगभग 10 बजे फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री में आग की लपटें उठने लगीं। कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई और कई मजदूर इस आग में झुलस गए। फैक्ट्री के स्पंज आयरन प्लांट के कोल कीलन में विस्फोट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में आग लगने से चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार, विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास काम कर रहे लोगों को संभलने तक का मौका तक नहीं मिला।

गवर्नर व राज्य सरकार के मतभेद पहले कभी-कभी सार्वजनिक होते थे

पर, अब, यह लगभग रोजमर्रा की घटना हो गई है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जनवरी। गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल ऐसे किरदार निभाते नज़र आ रहे हैं, जिन्हें परंपरागत रूप से विपक्षी नेताओं से जोड़ा जाता रहा है। इन घटनाक्रमों पर नज़र डालिए, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज राज्य विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित किए बिना ही विधानसभा से बाहर चले गए। उनकी मांग थी कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अभिभाषण के पाठ में शामिल केन्द्र सरकार की आलोचना करने वाले ग्यारह पैराग्राफ हटाए जाएँ।

दो दिन पहले, तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि ने भी मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण में ''तथ्यात्मक त्रुटियों और अप्रमाणित दावों'' का हवाला देते हुए, बिना संबोधन दिए सदन से वॉकआउट किया था। इसी प्रकार 20 जनवरी को ही केरल के राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर ने मंत्रिमंडल-स्वीकृत नीति भाषण के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से केन्द्र सरकार की आलोचना करने वाले अंशों, को नहीं पढ़ा और कथित तौर पर पिनारायी विजयन सरकार की मंजूरी के बिना, कुछ बिंदु जोड़ दिए।

हालाँकि शुरुआती वर्षों में निर्वाचित सरकारों और राज्यपालों के बीच छोटे-मोटे टकराव होते थे, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसे टकराव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में आरिफ मोहम्मद खान ने 61 पन्नों के अभिभाषण में से केवल पहला और आख़िरी अनुच्छेद ही पढ़ा था। पश्चिम बंगाल में, 2021-22 के दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा में अपने भाषण बार-बार बीच में ही समाप्त कर दिए थे, एक बार तो उन्होंने 25 पन्नों के भाषण की जगह केवल एक वाक्य ही पढ़ा।

ऐसे पुराने उदाहरण भी मौजूद हैं, 1965 में पश्चिम बंगाल की राज्यपाल पद्मजा नायडू विधानसभा से वॉकआउट कर गई थीं। वर्ष 1967 में राजस्थान के एक राज्यपाल ने अपने भाषण के कुछ हिस्से छोड़ दिए थे।

- **प.बंगाल की राज्यपाल पद्मजा नायडू ने 1965 में विधानसभा से वाक् आउट किया तथा 1957 में राजस्थान के तत्कालिक राज्यपाल ने सरकार द्वारा उनको विधानसभा में पढ़ने के लिए दिए गए भाषण के कुछ अंश नहीं पढ़े थे।**
- **पर, यह बात अब अनहोनी नहीं रह गई। हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चन्द गहलोत ने विधानसभा से ''वाक् आउट'' किया, बिना अपना भाषण पढे। उनकी मांग थी कि राज्यपाल के भाषण से उन ग्यारह अनुच्छेदों को हटा देना चाहिए, जो केन्द्रीय सरकार की निंदा कर रहे हैं।**
- **इस घटना के दो दिन पहले तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने भी ऐसा ही ''वाक् आउट'' किया। उन्होंने भाषण में मौजूद ''अशुद्धियोंक व अप्रमाणित दावे'' पर आपत्ति जताई। ऐसी ही घटना केरल में बीस जनवरी को हुई, जब राज्यपाल राजेन्द्र आरलेकर ने, मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत सरकारी नीति प्रतिपादित करने वाले भाषण में केन्द्रीय सरकार की निंदा करने वाले अंश पढ़ने से इंकार कर दिया तथा उक्त भाषण में कुछ अंश अपनी ओर से जोड़ दिए। वर्ष 2024 में केरल के तत्कालीन गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी ऐसा ही किया था। वर्ष 2021-2022 में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकड़ ने भी अपने भाषण में, जो राज्य सरकार ने उन्हें पढ़ने के लिए दिया था, केवल एक वाक्य पढ़कर अपनी जिम्मेवारी पूरी की थी।**
- **इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नबम रेबिया के मामले में स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि राज्यपाल अपनी सोच व मत का इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे मामले में, उन्हें वो ही भाषण पढ़ना चाहिए जो राज्य मंत्रिमंडल तैयार करके देता है।**

जहाँ विपक्ष द्वारा किये गये वॉकआउट राजनीतिक संकेत माने जाते हैं, वहीं राज्यपालों द्वारा उठाया गया ऐसा कदम संवैधानिक विचलन (कॉन्स्टीट्यूशनल रप्चर्स) के रूप में देखा जा सकता है। संवैधानिक विशेषज्ञों को चिंता है कि राज्यपालों का यह रवैया, जो कभी बहुत कम नज़र आता था, अब धीरे-धीरे एक स्वीकृत चलन और आम घटना बनता जा रहा है।

इसलिए सवाल उठता है: क्या राज्यपाल विधानसभा में दिए जाने वाले भाषणों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? इस संदर्भ में अक्सर 2016 के नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जाता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्वों का उपयोग कर निर्वाचित सरकारों को दरकिनार नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी कहा था कि राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते और उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।

'एआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तात्कालिकता समन्वित नीतियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मांग करती है। बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच, गेट्स ने भारत-अमेरिका साझेदारी को बदलते वैश्विक परिदृश्य में कुछ गिने-चुने भरोसेमंद आधारों में से एक बताया।

उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि ''अमेरिका और भारत के बीच मज़बूत संबंध की तर्कसंगतता अंतत: हावी होगी।''

उन्होंने भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा एआई को तेज़ी से अपनाने की क्षमता को इसकी प्रमुख ताकत बताया।

ग्रोथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बुनियादी मजबूती में विश्वास को दर्शाता है।

साथ ही, उद्योग जगत सरकार के राजकोषीय समेकन (फिस्कल कन्सॉलिडेशन) के मार्ग के साथ भी सहमत दिखाई देता है। लगभग 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि विकास को समर्थन देने वाले उपायों के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन पर भी भरोसा कायम है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908